'बिजली में सरप्लस स्टेट होगा बिहार'

जागरण ब्यूरो, पटना : ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि 2016 में बिहार विद्युत सरप्लस स्टेट (राज्य) हो जाएगा। जून 2013 से हर साल 500 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होगी। वे मंगलवार को विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक के तहत विभाग की 10.80 अरब रुपये की अनुदान मांग पेश कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पर्याप्त बिजली की उपलब्धता के लिए उत्पादन, संचरण एवं वितरण के क्षेत्र में एकसाथ काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने 4,000 मेगावाट के अल्ट्रा-मेगा पावर प्लांट को मंजूरी दी है, जिसके लिए रजौली एवं बांका में सर्वे चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त को यह एलान कर चुके हैं कि 2015 तक बिजली की स्थिति नहीं सुधरी, तो वोट मांगने नहीं आएंगे। उनके इस संकल्प के तहत विभाग और उसके अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। 90 प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मंत्री ने अगले कुछ सालों में होने वाले विद्युत उत्पादन का परियोजनावार ब्योरा पेश करते हुए कहा कि 2015 तक 5,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध रहेगी।

उनके अनुसार संचरण के क्षेत्र में पावर ग्रिड कारपोरेशन और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बीच अगले 25 साल का समझौता होगा। इस माह के अंत तक यह करार हो जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 38 में से 20 जिले का डीपीआर तैयार हो चुका है। 11 जिले के डीपीआर को मंजूरी मिल भी गई है, जिसके लिए 3,000 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। शत-प्रतिशत बीपीएल कवरेज होगा। एपीएल के ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। 71 शहरों के ट्रांसफार्मर, पोल एवं तार बदले जाएंगे जिस पर 5,000 करोड़ की राशि खर्च होगी। पटना में 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से सात शहरों में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम शुरू होगा। दक्षिण एवं उत्तर बिहार में ग्रिड बन रहे हैं ताकि नेशनल ग्रिड से सीधे बिजली ली जा सके। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट रजौली या बांका में लगेगा। चौसा एवं पीरपैंती में एनएचपीसी और कजरा में भारत सरकार-हिमाचल सरकार के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा पन बिजली के प्लांट लगेंगे। नई टेक्नोलोजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सदस्यों से तार की चोरी और गलत कनेक्शन रोकने एवं बिल भुगतान कराने में सहयोग की अपील की।

- विधानसभा में ऊर्जा मंत्री ने बताई समयसीमा-2016
- कहा-2013 से हर साल 500 मेगावाट का होगा इजाफा
- सीएम बोल चुके हैं कि 2015 तक न सुधरी बिजली तो नहीं मांगेंगे वोट
- उत्पादन, संचरण व वितरण पर हो रहा एकसाथ काम
- अल्ट्रा-मेगा पावर प्लांट के लिए रजौली व बांका में सर्वे
- 10.80 अरब रुपये की अनुदान मांग को मिली मंजूरी

प्रमुख परियोजनाएं जिनसे सूबे को मिलेगी बिजली

परियोजना	मेगावाट	साल
1.फ़ांटी एवं बरौनी	440	दिसंबर 2013
2. बाढ़ स्टेज-1	523	दिसंबर 2014
3. बाढ़ स्टेज-2	660	2015
4. मुजफ्फरपुर	390	दिसंबर 2014
5. डीवीसी	100	विस्तार मिल रहा है
6. बरौनी	500	2015

इन जिलों को ग्रामीण विद्युतीकरण का डीपीआर मंजूर

बांका, नवादा, पटना, गया, रोहतास, आरा, अररिया, सिवान, किशनगंज, नालंदा व पूर्णिया.